# श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल, राजस्थान का उद्बोधन

## राजस्थान राज्य का वार्षिक सत्र – 2020 एवं राजस्थान में एमएसएमईज और उद्योग के लिए चुनौतियां

दिनांक **27 फरवरी, 2020** समय प्रातः **11.15 बजे**

स्थान – होटल राजपूताना शेरेटन, जयपुर

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल जी, सी.आई.आई. उत्तरी क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री निखिल साहनी जी, सी.आई.आई के अध्यक्ष श्री आनन्द मिश्रा जी, सी.आई.आई नॉर्दन रीजन के रीजनल डॉयरेक्टर श्री अंकुर सिंह चौहान जी, सी.आई.आई राजस्थान स्टेट काउन्सिल के उपाध्यक्ष श्री विशाल बैद जी, सी.आई.आई के डॉयरेक्टर श्री नितिन गुप्ता जी, भाइयो, बहनो, पत्रकार बन्धुओ और छायाकार मित्रो।

राजस्थान भर के आये हुये इंडस्ट्री मैम्बर्स से संवाद का अवसर देने के लिए सी.आई.आई को धन्यवाद देता हूँ। आज सी.आई.आई का वार्षिक दिवस है। राजस्थान–एमएसएमईज् और इंडस्ट्री के लिए नये अवसर प्रदान करने वाला प्रदेश है। यह विषय महत्वपूर्ण होने के साथ ही मेरा प्रिय विषय भी है। भारत के विकास में सी.आई.आई कई सालों से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जब मैं केन्द्र में मंत्री था, तब मुझे सी.आई.आई से अनेक बार संवाद का अवसर मिलता था।

एमएसएमईज भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। एमएसएमईज विकास को बढावा, रोजगार सृजन, औद्योगिक गतिविधियों में विभिन्नता लाने और समान क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे रही है।

यह सैक्टर नवोदित उद्यमियों का पोषण करता है। अल्पविकसित उद्योगों में नवाचार करने को प्रेरित करता हैं। एमएसएमईज में विकास के अवसर मौजूद हैं, वहीं एमएसएमईज पर अपनी प्रभाव और दक्षता में सुधार करने के लिए काफी ज्यादा दबाव भी है।

एमएसएमईज को उनके शुरूआती और विकास के चरणों के दौरान टर्म लोन और वर्किंग केपिटल लोन के माध्यम से समय पर और पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 5 वर्षों में 7 प्रतिशत से अधिक की सतत् विकास दर रहने के बावजूद एमएसएमईज सेक्टर अपने आकार और व्यापार की प्रकृति के कारण आपरेशनल मुश्किलों से जूझ रहा है।

प्रमुख मुद्दों में पर्याप्त और समय पर ऋण की अनुपलब्धता, ऋण की उच्च लागत, आनुशंगिक (Collateral) आवश्यकताऐं, इक्विटी पूंजी तक सीमित पहुंच आदि शामिल है।

इस तरह के मुद्दों को हल करने के लिए इस क्षेत्र में निधियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी निकायों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा समर्थित विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं को रोल आउट किया गया।

क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान भारत के उत्तरी और पश्चिमी विकास केन्द्रो के मध्य स्थित है। दिल्ली, मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर (DMIC) का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से गुजरता है।

राजस्थान एक शांतिपूर्ण और राजनैतिक रूप से विकसित राज्य है। राजस्थान अनेक क्षेत्रों में लाभदायक निवेश के लिये अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।

राज्य में प्रचुर भौतिक संसाधन, समृद्ध खनिज संपदा, अधिक मात्रा में कृषि उपज, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्मित वस्तुओं का उत्पादन तथा उत्कृष्ट कौशल से परिपूर्ण युवा उपलब्ध है। एमएसएमई क्षेत्र विनिर्माण प्रसंस्करण गतिविधियों और लाभकारी सेवाओं के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं और राज्य को निवेश के लिये अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है।

सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र रोजकार सृजन, मूल्यवर्धन, आय का समान वितरण, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के साथ साथ निर्यात आय के माध्यम से आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हालांकि राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में अभी भी एक विशाल विकास क्षमता विद्यमान है, जो कि उचित दोहन और पोषण रणनीति के माध्यम से विशाल रोजगार सृजन के लिये लाभकारी हो सकती है। एक सकारात्मक राजनीतिक और सुदृढ आर्थिक परिदृश्य के कारण अगले दशक में भारत के दुनिया में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद हैं।

सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग उपक्रम (MSME) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे देश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने उत्पादन की राष्ट्रीय अनिवार्यता पूरा करने एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने में एक अहम भूमिका निभाता है।

इसके अलावा MSME क्षेत्र नये युग के उद्यमियों के विकास का पोषण और समर्थन करता है। जो भारत में विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यवसाय बनाने की क्षमता रखते है। Make in India के माध्यम से निवेश करने वाली देशी एवं विदेशी दोनों कम्पनियों के मौजूदा और भविष्य में व्यवसाय के विकास के लिये MSME रीढ की हड्डी साबित हो सकती है।

नए सूक्ष्म एवं लघु संस्थान व्यवसाय के इको सिस्टम के विकास को सक्षम एवं सुदृढ माध्यम बनायेगा जो कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता पूर्ण सही उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध कराने में लाभकारी होगा।

अगर MSME सेक्टर को सही दिशा एवं मार्गदर्शन दिय गया तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये रीढ की हड्डी साबित होगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने में तथा विकास प्रदान करने की क्षमता रखता है।

अगले दशक में MSME के नवाचार के माध्यम से उद्यमिता एवं विकास को बढावा दिया जाना एक प्राथमिकता है।

राजस्थान से निर्यात के लिए बडी क्षमता रखने वाले शीर्ष दस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है। कृषि और खाद्य उत्पाद, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स और कम्प्युटर साफ्टवेयर, प्लास्टिक और लिनोलियम, ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स, चमडा और चमडे के उत्पाद, आयामी पत्थर, ग्रेनाईट और लेख पत्थर, रासायनिक और संबंद्ध इंजीनियरिंग , रेडीमेड वस्त्र, रत्न और आभूषण क्षेत्र आदि।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत ने हालिया रिर्पोट में विश्व बैंक की ईज ऑफ डुंइंग बिजनेस रैकिंग में 63वी रैंक हासिल करने के लिए 14 पदों की छलांग लगाई। यह 2014 में 189 देशों में से 142वी रैंक से काफी सुधार है।

मैं राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कानूनों के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को हटाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए कानून के लिए राज्य सरकार को बधाई देता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द।